

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 201
No. 302]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939	[N.C.T.D. No. 201

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

जिला पश्चिम
(प्रशासक/ए.डी.एम. कार्यालय, जिला पश्चिम)

अधिसूचना
दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

अधिसूचना नं. एफ 8/02/15/एल. एण्ड बी./एल.ए./10621 के द्वारा दिनांक 28/08/2015 को [kl jk u- 74//21/4&16/ 22 /4&3/ 85//2@1/2&8/ 2@2/2&8/ 85//3@1/1&9/ dly jdck 15 ch?kk 04 fcLok fVdjh dlyk xk] स्थित जमीन को अधिग्रहण करने के लिए उचित व न्याययुक्त मुआवजा प्रदान करने के अधिनियम, 2013 धारा 16 के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्व्यवास्थापना योजना की प्रशासक की रिपोर्ट का प्रारूप

अधिसूचना नं. एफ 8/02/15/एल. एण्ड बी./एल.ए./10621 के द्वारा दिनांक 28/08/2015 को [kl jk u- 74//21/4&16/ 22 /4&3/ 85//2@1/2&8/ 2@2/2&8/ 85//3@1/1&9/ dly jdck 15 ch?kk 04 fcLok xk] स्थित भूमि मुल परियोजना यानी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र टिकरी कॅला के निर्माण के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवास्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अन्तर्गत अधिग्रहण करने की अधिसूचना विशेष सचिव (भू. एवं भ.) जी.एन.सी.टी. दिल्ली, भूमि एवं भवन विभाग, विकास भवन नई दिल्ली द्वारा जारी की गई थी । कलेक्टर/ जिलाधीश (पश्चिम) RFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर है ।

उपरोक्त अधिसूचना के मुताबिक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम को उपरोक्त अधिनियम की धारा 43 उप धारा (1) के अधीन उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों के पुनः स्थापन और पुनर्वास करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था ।

उपरोक्त RFCTLARR अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत प्रशासक को पुनर्वास और पुनर्व्यवास्थापना करने की योजना तैयार करनी चाहिए जैसा नीचे प्रस्तुत है ।

प्रशासक द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना ।

1. 16(1) कलेक्टर द्वारा धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक ऐसी रीति में और ऐसे समय भीतर जो विहित किया जाए, प्रभावित कुटुंबों का एक सर्वेक्षण कराएगा तथा उनकी जनगणना का कार्य हाथ में लेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा:-

(क) ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां, जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है;

(ख) ऐसे भूमि खोने वालों और भूमिहीनों की बाबत, जिनकी जीविका अर्जित की जा रही भूमि पर मुख्यतः निर्भर है, खो गई जीविका;

(ग) ऐसे लोकोपयोगी और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है जहां की प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य अंतर्वर्तित है ;

(घ) ऐसे सुख सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्योरे, जिन पर प्रभाव पड़ा है या जिनके प्रभावित होने की संभावना है, जहां कि प्रभावित कुटुंबों का पुनर्व्यवस्थापन कार्य अंतर्वर्तित है, और

(ङ) ऐसे किन्हीं सामान्य सम्पत्ति स्रोतों के ब्योरे, जिनका अर्जन किया जा रहा है ।

2. प्रशासक, उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण और जनगणना के आधार पर, विहित किए गए अनुसार एक प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करेगा जिसमें ऐसे प्रत्येक भू-स्वामी और भूमिहीन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियों की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी, जिनकी जीविका मुख्य रूप से अर्जित की जा रही भूमियों पर निर्भर है और जहां प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन अंतर्वर्तित है -

क. पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवन की सूची,

ख. ऐसी लोक सुख-सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के ब्योरे, जो पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जानी हैं ।

3. उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में कार्यान्वय के लिए समय सीमा सम्मिलित होगी ।

4. उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार द्वारा स्थानीय रूप में अवगत कराया जाएगा और संबंधित ग्राम सभाओं या नगरपालिकाओं में विचार विमर्श किया जाएगा ।

5. लोक सुनवाई, प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के लिए तारिख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात, ऐसी रीति में, विहित की जाए, की जाएगी

RFCTLARR, अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के तहत सुनवाई के लिए तत्कालीन कलेक्टर जिला पश्चिम द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को अधिगृहित की जाने वाली भूमि खसरा न. 74//21(4-16), 22 (4-3), 85//2/1(2-8), 2/2(2-8), 85//3/1(1-9) कुल रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा गाँव टिकरी कलां दिल्ली को सुनवाई हेतु दिनांक 16/5/2016 को नोटिस जारी किया और दिनांक 31/05/2016 को निम्नलिखित व्यक्ति सुनवाई के लिए उपस्थित थे ।

1. श्री महिपाल दराल, अधिवक्ता
2. श्रीमति सुमन लता
3. श्री संतोष तिवारी

जन सुनवाई के दौरान जो मुख्य आपत्तियां थी :

(i) RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) की अधिसूचना अवैध है क्योंकि अध्यादेश जिसके तहत इसे अधिसूचित किया गया था वह दिनांक 31/08/2015 को समाप्त हो गया है ।

(ii) अधिग्रहण के लिए जो कुल क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है, वह गाँव बिजवासन, काजीपुर, ककरोला और कैर की तुलना में बहुत अधिक है ।

(iii) अपशिष्ट भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था ।

आगे एक और सुनवाई दिनांक 09/06/2016 को तत्कालीन कलेक्टर जिला पश्चिम ने भूमिदारों द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर विचार के लिए आयोजित की गई थीं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

1. श्री महिपाल दराल, अधिवक्ता
2. श्री गजेन्द्र सिंह, भूमिदार

3. श्रीमति धनवंती
4. श्री सुखबीर (राजबाला)
5. श्री मनोज कुमार (रेखा) भूमिदार
6. श्री संदीप राणा, श्री सुरेन्द्र की ओर से (जी पी ए)
7. श्री राजबीर सिंह (राजबाला)
8. श्री संतोष तिवारी

इसके अलावा 31/05/2016 को सुनवाई के दौरान उठाई गई कुल दस आपत्तियां हैं लेकिन सुनवाई के बाद यह पता चला कि भूमिदारों द्वारा उठाई आठ आपत्तियां/मुद्दे कमोबेश समान हैं और मुख्य रूप से दो आपत्तियां उठाई गई जो निम्नप्रकार हैं ।

(i) अधिनियम की धारा 11(1) की अधिसूचना का प्रकाशन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं है और विशेष रूप से डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ के कार्यालय गाँव टिकरी कॅला दिल्ली के प्रभावित इलाके, चौपाल तथा सामुदायिक केन्द्र में नोटिस का कोई प्रकाशन नहीं किया गया ।

(ii) अध्यादेश 2015 की धारा 10ए(2) की कोई अनुपालना नहीं हुई जिसके तहत सरकार को अपशिष्ट भूमि का सर्वेक्षण किया जाना था यदि सर्वेक्षण किया गया होता तो निजी व्यक्तियों की भूमि को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित नहीं किया जाता ।

इसलिए तत्कालीन ए.डी.एम. (पश्चिम) ने प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 74//21(4-16), 22 (4-3), 85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1(1-9) कुल एकबा 15 बीघा 04 बिस्वा ग्राम टिकरी कलां दिल्ली का राजस्व क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित बी.डी.ओ. (पश्चिम) के साथ पंचायत सचिव गाँव टिकरी कलां तहसीलदार पंजाबी बाग के साथ हल्का पटवारी और फिल्ड कानूनगो गाँव टिकरी कलां के और पश्चिम जिले के भूमि अधिग्रहण शाखा के दोनों कानूनगो के साथ क्षेत्रीय सर्वेक्षण का आयोजन किया । आदेश संख्या LAC(प.)/2016/406 दिनांक 30/04/2016 के माध्यम से तहसीलदार पंजाबी बाग को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः-स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 16(1) के अनुरूप एक रिपोर्ट देने के लिए आदेश जारी किया गया था । फाइल संख्या LAC(प.)/ 2016/406 दिनांक 30/04/2016 से धारा 16(1) [भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार, 2013] के तहत सार्वजनिक सुनवाई एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आयोजन के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई । दिनांक 12/05/2016 को प्रभावित क्षेत्र गाँव टिकरी कलां में ए.डी.एम. (पश्चिम) तहसीलदार पंजाबी बाग, हल्का पटवारी, फिल्ड कानूनगो ग्राम टिकरी कलां दो कानूनगो LAC (पश्चिम) बी.डी.ओ. (पश्चिम) पंचायत सचिव ग्राम टिकरी कलां तथा ग्राम वासियों सहित सार्वजनिक सुनवाई व क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया ।

धारा 16(5) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार, 2013, पढ़ें नियम 7(6) मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवहार और विकास योजना नियम 2015 के तहत तत्कालीन ए.डी.एम. (पश्चिम) रामपुरा दिल्ली ने दिनांक 18/07/2016 को दिनांक 08/08/2016 की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया । जिसकी सूचना बजरिये पटवारी हल्का ग्राम टिकरी कलां प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी ।

उसके बाद दिनांक 08/08/2016 को धारा 16(5) भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार, 2013 पढ़ें नियम 7(6) तथा मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्व्यवहार और विकास योजना नियम 2015 के तहत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ग्राम टिकरी कलां में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में जन सुनवाई के लिए ए.डी.एम. (पश्चिम) कार्यालय रामपुरा दिल्ली निम्नलिखित व्यक्ति हाज़िर हुए:-

1. श्री गजेंद्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह
2. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री सुखबीर सिंह
3. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार
4. श्रीमती धनवंती पत्नी श्री अत्तर सिंह
5. श्री संदीप राणा पुत्र श्री राजेंद्र सिंह
6. श्री अनिल चौधरी, तहसीलदार (पंजाबी बाग)
7. श्री रणवीर सिंह, फिल्ड कानूनगो
8. श्री महेंद्र सिंह, VLW, O/o बी.डी.ओ. (पश्चिम)
9. श्री परमवीर, AE (सिविल), दिल्ली जल बोर्ड

जन सुनवाई में प्रभावित भूमिधरों के ब्यान दर्ज किये गए थे और प्रभावित लोगों के आधार कार्ड की फोटो कापी प्राप्त की गयी थी । प्रभावित भूमिधरने कुछ सूचनाएं दी जिन्हें रिकॉर्ड में रखा गया ।

(क) ऐसी भूमि और स्थावर संपत्तियों की विशिष्टियां, जिनका प्रत्येक प्रभावित कुटुंब से अर्जन किया जा रहा है ;

(अ) प्रभावित क्षेत्र के भूमिधारकों की सूची :-

अधिग्रहण करने योग्य कुल भूमि 15 बीघा 4 बिस्वा गांव टिकरी कलां दिल्ली खसरा नं. 74//21(4-16), 22(4-3),

85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1(1-9) भूमि का प्रकार- कृषि

खसरा न.	प्रभावित परिवार/कंपनी का नाम	रकबा/ हिस्सा	विवरण
74/21 (4-16)	मेसर्स के.सी.बी. बिल्डर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	4 बीघा 16 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	अभिलेख स्वामी
74/22 (4-03)	1. श्री गजेंद्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह 2. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री सुखवीर सिंह 3. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री राजवीर सिंह 4. श्रीमती रोशनी पत्नी श्री जगदीश 5. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार	1 बीघा 15 बिस्वा (पूरा हिस्सा) 1 बीघा 8 बिस्वा (5/14 हिस्सा) 1 बीघा 8 बिस्वा (5/14 हिस्सा) 1 बीघा 8 बिस्वा (4/14 हिस्सा) 1 बीघा (पूरा हिस्सा)	अभिलेख स्वामी
85/2/1(2-08)	मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि.	2 बीघा 8 बिस्वा	1. श्रीमती धनवंती पत्नी श्री अत्तर सिंह (1-08) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5309 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2278 दिनांक 27/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा 2. श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह (1-0) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5310 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2278 दिनांक 27/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा
85/2/2(2-08)	मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	2 बीघा 8 बिस्वा	1. श्रीमती सुमन लता पत्नी श्री सुनील कुमार (1-02) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5089 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2270 दिनांक 16/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा 2. श्री संतोष तिवारी पुत्र श्री मोहन तिवारी (1-06) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5115 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2271 दिनांक 17/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा
85/3/1(1-09)	1. मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज 2. मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज	09 बिस्वा 01 बीघा	श्री जी. एस. दराल पुत्र श्री जसवंत सिंह (09 बिस्वा) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5088 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2270 दिनांक 16/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा 2. श्री जी. एस. दराल पुत्र श्री जसवंत सिंह (1 बीघा) बराये सेल डीड पंजीकृत पंजीकरण संख्या 5152 किताब न. 1 वॉल्यूम न. 2272 दिनांक 18/12/2013 SR-IIA (पंजाबी बाग) द्वारा तामिल शुदा

ब. भवन पेड़ इमारत अन्य अचल संपत्ति या भूमि से जुड़ी संपत्ति या अधिग्रहण की जाने वाली इमारत की सूची :-

पेड़	:-	खसरा न. 74/21 (4-16) में दस (10) पेड़
पेड़ की किस्म	:-	01 जाटी (व्यास 02 फूट), 03 नीम (व्यास 02 फूट), 01 नीम (व्यास 01 फूट), 03 शहतूत (व्यास 01 फूट प्रत्येक), 01 शहतूत (व्यास 02 फूट), 01 लसोड़ा (व्यास 1.5 फूट)

अन्य अचल संपत्ति : सीमा की दीवार निम्नलिखित आयाम के अनुसार विद्यमान है:-

- (i) खसरा न. 74//21 (4-16) की पूर्वी सीमा पर 198 फूट लम्बी व 7 फूट ऊंची दीवार बनी है।
- (ii) खसरा न. 74//21 (4-16) में दक्षिणी सीमा पर 54 फूट लम्बी व 7 फूट ऊंची और 132 फूट लम्बी व 3 फूट ऊंची दीवार बनी है।
- (iii) खसरा न. 74//21 (4-16) की पूर्वी सीमा पर 42 फूट लम्बी व 7 फूट ऊंची दीवार बनी है।
- (iv) खसरा न. 85//2/2 व 3/1 में (अ) 8 फूट ऊंची चारदीवारी व 8 फूट ऊंची विभाजन की दीवार के साथ (ब) 1 कमरा 10 फूट X 12 फूट बिना छत के बना है (स) 1 अस्थायी टीन शेड 50 फूट X 20 फूट जो बांस से बना हुआ है के साथ 2 लोहे के गेट 16 फूट X 10 फूट और 20 फूट X 8 फीट मौजूद है (द) उत्तरी सीमा पर चारदीवारी लगभग टूटी हालत में है।

(ख) ऐसे भूमि खोने वालो और भूमिहीनों की बाबत, जिनकी जीविका अर्जित की जा रही भूमि पर मुख्यतः निर्भर है, खो गई जीविका:

सुनवाई और अन्य रिपोर्ट जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है के अनुसार निम्नलिखित प्रस्तुतियां हैं :-

1. श्री गजेंद्र सिंह दराल पुत्र श्री जसवंत सिंह खसरा न. 74//22 (1-15) और 85//3/1 (1-09) के मालिक है। उन्होंने अपने व्यापार में कहा कि उनका भूमि भवन विक्री व्यापार (Real Estate) का कारोबार है और कृषि क्रियाकलापों में शामिल है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं मिली।
2. श्रीमती राजबाला पत्नी श्री सुखबीर सिंह का खसरा न. 74//22 (1-08) में 5/14 भाग, श्रीमती राजबाला पत्नी श्री राजबीर सिंह का खसरा न. 74//22 (1-08) में 5/14 भाग के मालिक है। श्रीमती रोशनी पत्नी श्री जगदीश का खसरा न. 74//22 (1-08) में 4/14 भाग है ने अपने अधिवक्ता श्री महिपाल दराल द्वारा यह कहा कि वह सरसों के कृषि क्रियाकलापों को मजदूरों का उपयोग करके किया जाता है और उनके पास कुछ मामूली आय किराये से होती है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं मिली।
3. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार खसरा न. 74//22 (1-0) की मालिक है। उन्होंने कहा कि उनके पति का छोटा सा व्यापार है और तहसील बहादुरगढ़(हरियाणा) में रहते हैं तथा कृषि गतिविधि बारिश पर निर्भर करती है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं मिली।
4. श्री महिपाल सिंह दराल अधिवक्ता/प्रतिनिधि मेसर्स K.C.B. बिल्डर्स खसरा न. 74//21 (4-16) के मालिक है। उन्होंने कहा कि खसरा न. 74//21 (4-16) पर सरसों की खेती की गयी पटवारी के रिकॉर्ड गिरदावरी साल 2013-14 और 2014-15 से पुष्टि कर दी गयी। लेकिन गिरदावरी साल 2015-16 के रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी कृषि गतिविधि नहीं मिली और कंपनी का भूमि भवन विक्री व्यापार (Real Estate) का व्यवसाय है और साल 2014 में फार्म-हाउस (Farm-House) के विकास के उद्देश्य से जमीन खरीदी गयी है, लेकिन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक उस जमीन पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं मिली।
5. श्रीमती धनवंती पत्नी श्री अत्तर सिंह खसरा न. 85//2/1 (1-08) रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 27/12/2013 के जरिये मालिक होने का दावा करती हैं तथा उन्होंने कहा कि कृषि गतिविधियों के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं मिली।
6. श्री सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह खसरा न. 85//2/1 (1-0) मालिक होने का दावा करते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 27/12/2013 के जरिये उन्होंने कहा कि कृषि गतिविधियों के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं मिली।
7. श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री सुनील कुमार खसरा न. 85//2/2 (1-02) रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 16/12/2013 के जरिये मालिक होने का दावा करते हैं। और श्री संतोष तिवारी पुत्र श्री मोहन तिवारी खसरा न. 85//2/2 (1-06) रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 17/12/2013 के जरिये मालिक होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि कृषि गतिविधियों के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पटवारी की गिरदावरी वर्ष 2013-16 के रिकॉर्ड के अनुसार इस भूमि पर कोई कृषि गतिविधि नहीं पायी गयी।

स्थानीय जांच रिपोर्ट और सुनवाई में उपरोक्त भूमिदारों द्वारा दी गयी प्रस्तुति के अनुसार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दर्ज मालिकों की गाँव में अन्य भूमि है और इनके परिवार मुख्या रूप से गाँव में अपनी आजीविका के लिए इस जमीन पर निर्भर नहीं है और इनके आय के अन्य स्रोत हैं। सार्वजनिक सुनवाई व रिपोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, प्रभावित परिवार के सदस्यों ने अधिग्रहण की जा रही भूमि पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार को छोड़ कर दर्ज भूमिदारान के पास अतिरिक्त भूमि बचती है। इसलिए मेरी राय में कोई भी भूमिधर वास्तव में पूर्ण रूप से कृषि गतिविधियों में शामिल नहीं है। और ऐसे मामले में कोई भी आजीविका का नुकसान शामिल नहीं है।

प्रभावित क्षेत्र में व्यापार व व्यवसायों की सूची :- सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में कोई कृषि, व्यापार या व्यवसाय नहीं है।

प्रभावित क्षेत्र में अनु. जा./अनु.ज.जा./ विक्लांग :- शून्य

या शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों की सूची

(ग) ऐसे लोकोपयोगी और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हुए हैं या जिनके प्रभावित होने की संभावना है जहां की प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्व्यवस्थापन का कार्य अंतर्बलित है :

भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृषि भूमि है जो केवल कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। RR सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रभावित क्षेत्र में कोई फसल खेती और कटाई योग्य नहीं पायी गयी। कोई भी रिहायशी मकान/मानव बस्ती प्रभावित नहीं हो रही है इसीलिए इसे विस्थापन वाले परिवारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए इससे प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण से कोई भी सार्वजनिक उपयोगिता प्रभावित नहीं है तथा सरकारी भवन मौजूद नहीं है।

इसे लागू नहीं है के रूप में समझा जाये।

1/2K1/2, d s l q k l f o/kkvka vk\$ vol j pukRed l f o/kkvka ds C; kj\$ ftu ij i Hkko i Mk g\$; k ftuds i Hkfor kaus dh l Hkkouk g\$ tgka fd i Hkfor d/pka dk i q; bLFkiu dk; Lvrnfyr g\$;

भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक कृषि भूमि है जो केवल कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। RR सर्वेक्षण और सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रभावित क्षेत्र में कोई फसल खेती और कटाई योग्य नहीं पायी गयी। विस्थापन वाले परिवारों के श्रेणी में कोई रिहायशी मकान और परिवारों को प्रभावित नहीं किया जा रहा है। इसलिए इससे प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास लागू नहीं है। इसके अलावा अधिग्रहण से कोई भी सार्वजनिक उपयोगिता प्रभावित नहीं है तथा सरकारी भवन मौजूद नहीं है।

इसे लागू नहीं है के रूप में समझा जाये।

1/2K1/2, d s fdUgh l kekU; l Ea fr L=kvrka ds C; kj\$ ftudk vtlu fd; k tk jgk g\$A

इसको लागू नहीं समझा जाये।

गाँव सभा व गाँव पंचायत के साथ संवाद :-

गाँव टिकरी कलां में कोई भी निर्वाचित पंचायत नहीं है। निर्वाचित गाँव पंचायत/गाँव सभा न होने के कारण खंड विकास अधिकारी को गाँव के विकास के लिए अधिकृत किया गया है। RR सर्वेक्षण के दौरान श्री आर.पी. सिंह बी.डी.ओ. (पश्चिम) और श्री नरेश कुमार पंचायत सचिव उपस्थित थे तथा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान बी.डी.ओ. (पश्चिम) के प्रतिनिधि श्री महेंदर सिंह, VLW उपस्थित थे।

पुनर्वास एवं पुनः स्थापना योजना

RFCTLARR अधिनियम 2013, अध्याय VI प्रक्रिया एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापना का तरीका धारा 43 के अनुसार निम्नहस्ताक्षरित को पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का रूपरेखा बनाने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना(आर. आर. स्कीम) धारा 16,17, 18, 19, 31, 41 और 42 (यदि मान्य है), 43, RFCTLARR अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची और नियम 7, 8, 9 (यदि मान्य है) 16, फार्म IV (यदि मान्य है) और RFCTLARR (मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन और विकास योजना) नियम, 2015 के फार्म VII के अनुरूप रूपरेखा तैयार किया जा रहा है।

उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर यह समझा जाता है कि प्रभावित परिवारों / कंपनियां :

(1) मैसर्स के.सी.बी. बिल्डर्स और डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास खसरा नंबर 74/21(4-16) अधिगृहित भूमि के अतिरिक्त 05-05 बीघा ज़मीन बचती है।

(2) श्री गजेन्द्र सिंह दराल पुत्र श्री जसवंत सिंह खसरा न. 74//22 (1-15) के अतिरिक्त 10-03 बीघा कृषि भूमि और 15 बिस्वा भू खंड विस्तृत आबादी में है।

(3) श्रीमती राजबाला पत्नी श्री सुखवीर सिंह और श्रीमती राजबाला पत्नी श्री राजवीर सिंह दोनों भुमिदार 5/14 भाग, श्रीमती रोशनी पत्नी जगदीश 4/14 भाग के खसरा न. 74//22 (1-08) में मालिक है। प्रत्येक भूमिधर के पति के पास 05 बीघा कृषि भूमि और 13 बिस्वा का भू खंड विस्तृत आबादी में है।

(4) श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार खसरा न. 74//22 (1-0) के मालिक है जो बहादुर गढ़ (हरियाणा) की निवासी है, इस ज़मीन के अलावा गाँव में अन्य भूमि नहीं है।

(5) मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि. खसरा नंबर 85//2/1(2-08), मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज खसरा नंबर 85//2/2(2-08), 85//3/1(0-09), मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज खसरा न. 85//3/1(1-00) राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक है परन्तु दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सेल डीड के अनुसार कंपनी ने अपनी ज़मीन वर्ष 2013 में बेच दी है।

प्रभावित परिवार/दर्ज किये गए स्वामियों में श्रीमती रेखा पत्नी मनोज कुमार को छोड़ कर सभी के पास अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त भूमि गाँव में है। मेरी राय में प्रभावित परिवार, विस्थापित परिवार की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि सभी के पास ग्राम टिकरी कलां में रिहायशी आवास है और अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त भूमि है। कोई भी भुमिदार पूर्ण रूप से कृषि क्रिया में लिस नहीं है तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कृषि पर पूर्णतः निर्भर नहीं है। RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 3(K) के अनुसार "विस्थापित परिवार" का अर्थ है किसी भी परिवार को जो भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित किया जाता है व अधिग्रहित भूमि के स्थान पर दूसरी जगह पुनः स्थापित किया जाता है। इस मामले में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वह कृषि भूमि है और उसके बदले भूमि अधिग्रहण आयुक्त (इस मामले में उपायुक्त पश्चिम) द्वारा अवार्ड उद्घोषित करने पर मुआवज़ा दिया जाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रभावित परिवार की विस्थापना व पुनर्स्थापना की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उनको अपने रिहायशी मकानों से विस्थापित नहीं किया जा रहा है केवल कृषि भूमि ही अधिग्रहण की जा रही है। हालाँकि, मेरे विचार से इस योजना में प्रभावित परिवार का कोई भी पुनः स्थापना का केस नहीं बनता है। मेरी समझ से प्रभावित परिवार केवल पुनर्वास के लिए विचारनीय है।

पुनर्वास और पुनः स्थापना स्कीम दूसरी अनुसूची के आधार पर तैयार की गयी है (ऐसे तत्त्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची में उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुम्बों (ऐसे भू-स्वामी और कुटुम्ब दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना हकदारी के तत्व) दूसरी अनुसूची के आधार पर पुनर्वास व पुनः स्थापना योजना की रूपरेखा तैयार की गयी है और संलग्न प्रारूप में संक्षिप्तीकरण है और RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 17 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को समीक्षा करने के लिए आग्रह किया गया है।

प्रभावित परिवारों/भुमिदार/कंपनी के प्रतिनिधियों ने जन सुनवाई के दौरान भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई और यह रिकॉर्ड में उनके बयानों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

संक्षिप्त नमूना व पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन योजना (सभी प्रभावित परिवारों के हक में पुनर्वास एवम् पुनर्व्यवस्थापन के तत्व)

1	योजना का नाम: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा गाँव टिकरी कलां ज़िला पश्चिम, दिल्ली में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना						
2	पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम व उनके द्वारा किए गए दावों की प्राकृति: जैसे क्रमांक 4 में है।						
3	प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन के हक के लिए दी गयी समय सीमा RFCTLARR ACT 2013 की धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड उद्घोषित करने की तिथि के 18 महीने के अंतर्गत						
4	दावेदार का नाम/प्रभावित परिवार/कंपनी	आयु/जन्म तिथि	पिता/पति का नाम	आधार नंबर	व्यवसाय	पुनर्वास व पुनः स्थापना का अधिकार	टिप्पणी
i	मेसर्स के.सी.बी. बिल्डर्स & डेवलपर्स प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	रियल एस्टेट का कारोबार	(i) विस्थापना के मामले में रिहायशी मकान देने की व्यवस्था	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
ii	श्री गजेन्द्र सिंह दराल	1976	पुत्र श्री जसवंत सिंह		रियल एस्टेट का कारोबार	(ii) भूमि का आवंटन किया जाना	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण सिंचाई योजना के लिए नहीं है।
						(iii) विकसित भूमि देने का प्रस्ताव	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण शहरीकरण के लिए नहीं है।

iii	श्रीमती राज बाला		पत्नी श्री सुखवीर सिंह		सेवनिर्वित शिक्षिका	(iv) वार्षिक भत्ता/नौकरी	संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किये जाए। (क) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाए अथवा किसी अन्य वांछित योजना में रोजगार की व्यवस्था की जाए और उस क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कुशलता प्रदान करें अथवा न्यूनतम मजदूरी दर जो कि किसी विशेष समय लागू है न्यूनतम मजदूरी दर से कम न हो पर रोजगार के प्रावधान करें। (ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपए का अनुदान (ग) प्रभावित परिवार को 2,000 रुपए प्रति महीने की दर से 20 साल तक वार्षिक भत्ता प्रदान किया जायेगा (जो कि मुद्रास्फीति के अनुसार प्रतिवर्ष समायोजित किया जायेगा।
iv	श्रीमती राज बाला		पत्नी श्री राजवीर सिंह		किसान	(v) प्रभावित परिवार को जीवन निर्वाह हेतु 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
v	श्रीमती रेखा	1986	पत्नी श्री मनोज कुमार		व्यपारी	(vi) विस्तारित परिवार के पुनः स्थापना के लिए परिवहन के व्यय प्रदान करना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
vi	श्रीमती रोशनी		पत्नी श्री जगदीश		किसान	(vii) पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान की लागत	लागू नहीं है क्योंकि कोई भी पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान प्रभावित क्षेत्र में नहीं है।
Vii	मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	(viii) किसी कलाकार, छोटा व्यापार व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नहीं है क्योंकि अधिग्रहण प्रभावित भूमि में गैर कृषि/व्यवसायिक/ औद्योगिक ढांचा नहीं है।
Viii	मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	(ix) मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं है यह सिंचाई या हाइडल परिवारों नहीं है।
ix	मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	(x) पुनः स्थापना के लिए एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवारों को एक मुश्त केवल रुपए 50,000/- दिए जाएँगे।

X	मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	(xi) स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क, यदि दिया है।	यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) वहन करेगा
---	------------------------------	------------	------------	------------	------------	--	---

सुरेश चंद मीणा, प्रशासक (आर.आर.)

REVENUE DEPARTMENT

(OFFICE OF THE ADMINISTRATOR/ADM, DISTRICT WEST)

NOTIFICATION

Delhi, The 8th August, 2017

F. No. LAC(W)/ Misc./2017/3879.—Draft Report of Administrator for Rehabilitation and Resettlement Scheme U/s 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 of families affected with the proposed acquisition of land Khasra no. 74//21(4-16), 22(4-3), 85//2/1(2-8), 2/2(2-8), 85//3/1(1-9) total area 15 bigha 04 biswa Village Tikri Kalan for Construction of Waste Water Treatment Plant at Tikri Kalan.

Vide notification no F.8/2/15/L&B/LA/10621 dated 28/08/2015 issued by Special Secretary (L & B), GNCT of Delhi, Land & Building Department, Vikas Bhawan, New Delhi in respect of acquisition of land for public purpose bearing Khasra no. 74//21(4-16), 22(4-3), 85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1 (1-9) total measuring 15 Bigha 04 Biswa land of village Tikri Kalan was notified U/s 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 for infrastructure project i.e. Construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) in Village Tikri Kalan, Collector/DC(West) is the Land Acquisition Collector under the RFCTLARR Act, 2013.

Vide above mentioned notification, Addl. District Magistrate(West) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for rehabilitation & resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.

As per section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, preparation of Rehabilitation & Resettlement Scheme by the Administrator should be done and the same is reproduced as below:-

Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme by the Administrator

- Upon the publication of the preliminary notification under sub – section(1) of section 11 by the Collector, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall conduct a survey and undertake a census of the affected families, in such manner and within such time as may be prepared, which shall include.
 - Particulars of lands and immovable properties being acquired of each affected family.
 - Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihoods are primarily dependent on the lands being acquired.
 - A list of public utilities and Govt. buildings which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.
 - Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved.
 - Details of any common property resources being acquired.
- The administrator shall, based on the survey and census under sub section (1), prepare a draft Rehabilitation & Resettlement Scheme, as described which shall include particular of the Rehabilitation & Resettlement entitlements of each land owner and land less whose livelihoods are primarily dependent on the lands being acquired and where resettlement of affected families are involved.

- i. A list of Govt. building to be provide in the Resettlement area,
- ii. Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the resettlement area.
3. The draft Rehabilitation & Resettlement Scheme referred to sub section (2) shall include time limit for implementing Rehabilitation & Resettlement Scheme.
4. The draft Rehabilitation & Resettlement Scheme referred to sub section (2) shall be made known locally by wide publicity in the affected area and discussed in the concerned Gaon Sabha & Municipalities.
5. A public hearing shall be conducted in such a manner as may be prescribed, after giving adequate publicity about the date, time and venue for the public hearing at the affected area.

Hearing under section 15(1) of the RFCTLARR,2013 was done by the then Collector, District West in respect of Acquirement of land bearing Khasra No. 74//21 (4-16), 22(4-3), 85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1(1-9), Village Tikri Kalan, Delhi on 31/05/2016 after being served notices to the affected parties on 16/05/2016. The following persons were present for hearing:-

1. Sh. Mahipal Drall, Advocate
2. Smt. Suman Lata
3. Sh. Santosh Tiwari

During the hearing, the main objections were:-

- i). The Notification of u/s 15 (1) of the RFCTLARR Act, 2013 is illegal since the ordinance under which it was notified has lapsed on 31/08/2015.
- ii) The total area being proposed for acquisition is to high as compare to Village Bijwasan, Kazi Pur, Kakrolla and Kair.
- iii) No survey of waste land was made.

Further, an another hearing was also held on 09/06/2016 by the then Collector, District West for consideration of objections raised by the Bhumidars. The following persons were present:-

1. Sh. Mahipal Drall, Advocate
2. Sh. Gajender Singh, Bhumidar
3. Smt. Dhanwanti
4. Sh. Sukhbir (Rajbala)
5. Sh. Manoj Kumar (Rekha), Bhumidar
6. Sh. Sandeep Rana on behalf of Sh. Surender as GPA
7. Sh. Rajbir Singh (Rajbala)
8. Sh. Santosh Tiwari

Besides, objections raised in the hearing held on 31/05/2016, there are total ten objections in all but after hearing, it came to know that eight objections/issues raised by the bhumidars are more or less are same and mainly following two objections were raised.

- (i). The publication of the notification u/s 11 (1) of the Act is not in accordance with the provision of the Act and in particular, there is no publication of the notice in the office of the D.M., ADM, SDM, Tehsildar, BDO, in the affected area of Village Tikri Kalan and in Chaupal as well as in Community Centre.
- (ii). There has been no compliance of the section 10A (2) of the Ordinance, 2015 which mandates the Government to undertake the survey of the waste land. Had the survey been done, the land of private persons may not have been notified for acquisition.

Therefore, the then ADM (West) conducted a field survey of proposed land on 74//21 (4-16), 22(4-3), 85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1(1-9), Village Tikri Kalan, Delhi with revenue field staff included BDO (West) along with Panchayat Secretary of Village Tikri Kalan, Tehsildar (Punjabi Bagh) alongwith Halka Patwari & Field Kanungo

of Village Tikri Kalan and both Kanungos of Land Acquisition Branch, West District. An order vide No. LAC (W)/2016/406 Dated 30/04/2016 was issued to obtain a report on section 16(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 from Tehsildar (Punjabi Bagh). A public notice for conducting a public hearing and field survey as prescribed under section 16(1) for the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 & rule 7 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 (Compensation, Rehabilitation and Resettlement & Development Plan) rules, 2015 was issued vide file No. LAC (W)/2016/406 dated 30.04.2016 and public hearing and field survey was conducted on 12.05.2016 in the affected area in Village Tikri Kalan in presence of the then ADM (West), Tehsildar (Punjabi Bagh), Halka Patwari & Field Kanungo of Village Tikri Kalan, 02 Kanungos LAC (West), BDO (West) alongwith Panchyat Secretary of Village Tikri Kalan and the Villagers of Village Tikri Kalan, Delhi.

The hearing notice u/s 16(5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read under Rule 7(6) Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement and development plan rules, 2015 was issued on 18/07/2016 for 08/08/2016 in the office of the then ADM (West), Ram Pura, Delhi ensuring it is brought to the knowledge of the affected parties through concerned Halka Patwari of Village Tikri Kalan.

Thereafter on 08.08.2016 in the office of the then ADM (West), Ram Pura, Delhi, at the time of hearing following persons were present on the date of public hearing u/s 16(5) of RFCTLARR Act, 2013 read with Rule 7(6) RFCTLARR Rules, 2015 for land acquisition under the new Act, for construction of Water Waste Plant by Delhi Jal Board at Village Tikri Kalan.

1. Sh. Gajender Singh S/o Sh. Jaswant Singh
2. Smt. Raj Bala W/o Sh. Sukhbir Singh
3. Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar
4. Smt. Dhanwanti W/o Sh. Attar Singh
5. Sh. Sandeep Rana S/o Sh. Rajender Singh
6. Sh. Anil Chaudhary, Tehsildar (Punjabi Bagh)
7. Sh. Ranbir Singh, Field Kanungo
8. Sh. Mahender Singh, VLW, O/o the BDO (West)
9. Sh. Paramveer, AE (Civil), Delhi Jal Board

In the public hearing, the statements of affected Bhumidhars were recorded and photocopies of Aadhaar Card of the affected persons were obtained. The affected parties/ bhumidhar had given certain information during hearing which are been kept in record.

(A). Particulars of lands and immovable being acquired of each affected family:

a. List of land holding in the affected area:

Total land being acquired: Khasra No. 74//21(4-16), 22(4-3), 85//2/1(2-8), 85//2/2(2-8), 85//3/1(1-9), nature of land Agriculture.

Khasra No.	Name of the affected family/ Company	Area/ Share	Remarks
74/21 (4-16)	1. M/s K.C.B.Builders & Developers Pvt. Ltd.	4 Bigha 16 Biswa (full share)	Recorded owner
74/22 (4-03)	1. Sh. Gajender Singh S/o Sh. Jaswant Singh 2. Smt. Rajbala W/o Sh. Sukhbir Singh 3. Smt. Rajbala W/o Sh. Rajbir Singh 4. Smt. Roshni W/o W/o Sh. Jagdish 5. Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar	01 Bigha 15 Biswa(full share) 01 Bigha 08 Biswa (5/14 share) 01 Bigha 08 Biswa (5/14 share) 01 Bigha 08 Biswa (4/14 share) 01Bigha (full share)	Recorded owner

85/2/1 (2-8)	M/s Kanihiya Trading & Investment Co. Pvt. Ltd.	02 Bigha 08 Biswa	<p>1. Sale deed vide regn. No. 5309 Book No. 1, Vol. No. 2278 dated 27/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Smt. Dhanwati W/o Sh. Attar Singh (1-08)</p> <p>2. Sale deed vide regn. No. 5310 Book No. 1, Vol. No. 2278 dated 27/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Sh. Surender Singh S/o Sh. Kartar Singh (1-00)</p>
85/2/2 (2-08)	M/s Surbhi Resources	02 Bigha 08 Biswa	<p>1. Sale Deed vide regn. No. 5089 Book No. 1, Vol. No. 2270 dated 16/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Smt.Suman Lata W/o Sh. Sunil Kumar (1-02)</p> <p>2. Sale Deed Vide regn. No. 5115 Book No. 1, Vol. No. 2271 dated 17/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Sh. Santosh Tiwari S/o Sh. Mohan Tiwari(1-06)</p>
85/3/1 (1-09)	<p>1. M/s Surbhi Resources</p> <p>2. M/s Saraswati Industries</p>	<p>(09 Biswa)</p> <p>(01Bigha)</p>	<p>1. Sale Deed Vide regn. No.5088 Book No. 1, Vol. No. 2270 dated 16/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Sh. G.S. Drall S/o Sh. Jaswant Singh (09 Biswa)</p> <p>2. Sale Deed Vide regn. No.5152 Book No. 1, Vol. No. 2272 dated 18/12/2013 regd. At SR- II A (Punjabi Bagh) executed in favour of Sh. G.S. Drall S/o Sh. Jaswant Singh (01 Bigha)</p>

b. List of trees, building, other immovable property or assets attached to the land or building being acquired:

Trees: 10 (Ten) in Khasra No. 74//21 (4-16)

Kind of Trees: 01 Jati (Biyas 02 Ft.), 03 Neem (Each having Biyas 02 Ft.), 01 Neem (Biyas 01 Ft.), 03 Sehtoot(Each having Biyas 01 Ft.), 01 Sehtoot (Biyas 02 Ft.), 01 Lasora(Biyas 1.5 Ft.)

Other immovable properties of Assets: Boundary wall exists as per following dimension:

- i. In Eastern side: Cemented Boundary wall of 198 ft. in length, 7 ft. height in Khasra No. 74//21(4-16)
- ii. In Southern side: Cemented Boundary wall of 54 ft. in length, 7 ft. height and 132 ft. length & 3 ft. height in Khasra No. 74//21(4-16)
- iii. In Northern side: Cemented Boundary wall of 42 ft. in length, 7 ft. height in Khasra No. 74//21(4-16)
- iv. In Khasra No. 85//2/2 & 85//3/1: (a) Four sided Cemented boundary wall of 8 ft. height with partition wall of 8 ft. height (b) one room measuring 10 ft. X 12 ft. without roof also exists (c) one temporary tin shed of 50 ft. X 20 ft. with wooden bambooes with two iron gates measuring 16 ft. X 10 Ft. and 20ft. X 8 ft. is exists (d) the boundary wall on the northern side is almost in broken condition.

(B). Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihoods are primarily dependent on the lands being acquired:

As per the hearing and other reports placed in record the submissions are as under :-

- (1) Sh. Gajender Singh Drall S/o Sh. Jaswant Singh owner of Kh. No. 74/22 (1-15), Kh.No. 85/3/1(1-9) stated in his statement that he has own real estate business and involved in agricultural activities but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.
- (2). Smt. Raj Bala W/o Sh.Sukhbir Singh owner of 5/14 share in Kh. No. 74/22(1-08), Smt. Raj Bala W/o Sh. Rajbir singh owner of 5/14 share in Kh. No. 74/22(1-08), Smt. Roshni W/o Sh. Jagdish owner of 4/14 share in Kh. No. 74/22(1-08) through their Counsel Sh. Mahipal Singh Drall have stated that agricultural activity of Mustard seed is undertaken by using labour and they have some marginal income from rent but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.
- (3). Smt.Rekha W/o Sh. Manoj Kumar owner in Kh. No. 74/22(1-00) has stated that her husband has a small business and resides in Tehsil Bahaudur Garg (Haryana) and agriculture activity depends upon the rain but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.
- (4). Sh. Mahipal Singh Drall represented M/s K.C.B owner in Kh. No. 74/21(4-16) has submitted that the Mustard seeds have been cultivated on the said land and same has been confirmed from Girdawari Record of Patwari for the year 2013-14 & 2014-15 but no agriculture activity has been found in the year 2015-16. Further, the company has a business of real estate and brought the land in the year 2014 for the purpose of development into farm house but as per the survey report, there is no such activity found on the said land.
- (5). Smt. Dhanwati W/o Sh. Attar Singh claims to be owner of 1-08 Bigha comprising in Khasra No 85/2/1 through registered sale deed dated 27/12/2013 has stated that agricultural activity is undertaken by using labour but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.
- (6). Sh. Surender Singh S/o Sh. Kartar Singh claims to be owner of 1-00 Bigha comprising in Khasra No 85/2/1 through registered sale deed dated 27/12/2013 has stated that agricultural activity is undertaken by using labour but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.
- (7). Smt. Suman Lata W/o Sh. Sunil Kumar claims to be owner of (1-02) comprising in Kh. No. 85/2/2 through registered sale deed dated 16/12/2013 and Sh. Santosh Tiwari S/o Sh. Mohan Tiwari(1-06) comprising in Kh. No. 85/2/2 through registered sale deed dated 17/12/2013 have stated that agricultural activity is undertaken by using labour but as per Girdwari Report of Patwari, no agriculture activity was found on the said land during the period year 2013-16.

As per local inquiry report and submissions made by the owner of above bhumidars in the hearings, it is evident that the recorded owners have other land in the village and their family are not primarily dependent on this land for their livelihood in the village and that they have other sources of income. As per the statements in the public hearing, member of the affected family, do not raised any objection to the land being acquired and recorded owners have additional land left with them except Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar. In my opinion, no bhumidhars are actually actively involved in agricultural activities and no livelihood loss is involved in such cases.

List of trade or businesses in the affected area:- No trade/business/ agriculture in the affected area as on date of survey.

List of persons belonging to SC/ST/Handicapped or physically challenged persons in the affected area:- Nil

(C) . A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved: Nil

The proposed land for acquisition is an agricultural land which is used for cultivation purpose only. At the time of RR survey and public hearing no crop was found been cultivated in affected area. **No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected family may not be considered in the category of displaced families. Therefore resettlement is not be applicable for this affected family.** Also the acquisition does not affected any amenities and infrastructural facilities as none exist.

This may be treated as Not Applicable.

(D). Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved:

The proposed land for acquisition is an agricultural land which is used for cultivation purpose only. At the time of RR survey and public hearing no crop was found been cultivated in affected area. **No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected family may not be considered in the category of displaced families. Therefore resettlement is not be applicable for this affected family.** Also the acquisition does not affected any amenities and infrastructural facilities as none exist.

This may be treated as Not Applicable.

(E). Details of any common property resource being acquired:

Not applicable

Consultation with Gram Panchayat/ Gram Sabha

There is no elected Gram Panchayat for village Tikri Kalan, in absence of an elected Gram Panchayat/ Gram Sabha, the Block Development Officer is entrusted with the development of the village. During the RR Survey Sh. R.P. Singh, BDO (West) and Sh. Naresh Kumar, Panchayat Secretary were present and during the public hearing BDO representative Sh. Mahender Singh, VLW was presented.

REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME

As per chapter VI, procedure and manner of Rehabilitation & Resettlement Scheme 43 of RFCTLARR Act, 2013 the undersigned has been appointed as the Administrator for drafting Rehabilitation & Resettlement Scheme. This Rehabilitation & Resettlement Scheme (RR Scheme) is being drafted in consonance with section 16,17,18,19,31,41 & 42 (if applicable), 43, Second Schedule of RFCTLARR Act, 2013 and rules 7,8,9, (if applicable) 16, Form IV (if applicable) and Form VII and RFCTLARR(Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules 2015.

Based on the available facts and records, it is understood that the affected families/companies

(1) M/s K.C.B. Builders & Developers Pvt. Ltd. Khasra No. 74/21(4-16) also have 05-05 Bigha land besides the said mentioned acquired land.

(2) Sh. Gajender Singh Drall S/o Sh. Jaswant Singh owner of Kh. No. 74/22 (1-15), also has 10-03 Bigha agriculture land and plot measuring 15 Biswa in extended abadi.

(3) Smt. Raj Bala W/o Sh.Sukhbir Singh and Smt. Raj Bala W/o Sh. Rajbir singh both owners of 5/14 share, Smt. Roshini W/o Sh. Jagdish owner of 4/14 Share in Kh. No. 74/22(1-08), the husbands of each bhumidhar have 05 Bigha agriculture land and plot measuring 13 Biswa in extended abadi.

(4). Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar owner in Kh. No. 74/22(1-00) lives in Bahadur Garh (Haryana) for their livelihood, besides this land she will be left with no other land in the village.

(5). M/s Kanhiya Trading and Investment Pvt. Ltd. Kh. NO. 85//2/1(2-08), M/s Surbhi Resources Kh. No. 85//2/2 (2-08), 85//3/1 (0-09), M/s Saraswati Industries Kh. No. 85//3/1 (1-00) are recorded owners in the Revenue Record but as per their sale deeds submitted by the claimants, the companies have sold their land in the year 2013.

The affected family / recorded owners except Smt. Rekha W/o Sh. Manoj Kumar have additional land apart from the land being acquired in the village. **I am of the opinion that the affected family may not be in the category of "Displaced Family" because they have a residential accommodation in Village Tikri Kalan and are also left with other land apart from the land being acquired.** No bhumidhar is actively involved in agriculture activities and rest of the members of the family are not primarily dependent on the land being acquired. As per the section 3(k) of RFCTLARR Act, 2013, "Displaced Family" means any family who on the affected area to the resettlement area. In the present case the land being acquired is an agricultural land for which compensation shall be paid as and when the land acquisition collector (Deputy Commissioner West in this case) announces the Award. Therefore, it is evident that the affected family may not need relocation and resettlement since they are not being displaced from their residential house, only agricultural

land is being acquired. However, I am of the opinion no case for Resettlement is made out in this particular affected family. I am of the opinion that the affected family may be considered for Rehabilitation only.

The Rehabilitation and Resettlement Scheme is prepared based on the Second Schedule (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES (BOTH LAND OWNERS AND THE FAMILIES WHOSE LIVELIHOOD IS PRIMARILY DEPENDENT ON LAND ACQUIRED) IN ADDITION TO THOSE PROVIDED IN THE FIRST SCHEDULE). Based on the second schedule the Rehabilitation and Resettlement Scheme is drafted, and summarized in the format (enclosed) and recommended for review by Land Acquisition Collector u/s 17 of RFCTLARR Act, 2013.

There is no objection raised by the affected families/ Bhumidars/Representatives of Companies in the public hearing with regard to the land being acquired and same is submitted by their statements in the record.

Summary format for Rehabilitation and resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

1.	Name of the project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Tikri Kalan, West Distt.						
2.	Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for Rehabilitation & Resettlement: As in Sl. No. 4						
3.	Time limit for provisions of Resettlement and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR Act 2013						
4.	Name of claimants/ affected family/Company	Age/ DOB	Father's/ Husband Name	Aadhar No.	Occupation	Rehabilitation & Resettlement entitlements	Remarks
i.	M/s K.C.B Builders & Developers Pvt. Ltd.	NA	NA	NA	Real Estate Business	i. Provisions of housing units in case of displacement	1. NA as there is no displacement for affected family.
ii.	Sh. Gajender Singh Drall	1976	S/o Sh. Jaswant Singh Drall		Real Estate Business	ii. Land to be allotted	2. NA as it is not an irrigation project.
iii.	Smt. Raj Bala		W/o Sh. Sukhbir Singh		Retired Teacher	iii. Offer for Developed Land	3. NA as land is not being acquired for urbanization purpose.
iv.	Smt. Raj Bala		W/o Sh. Rajbir Singh		Farmers	iv. Annuity/ Employment	4. The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with the following option:- a. Job may be given to at least one member per affected family in project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in required field or make provisions for employment at a rate not lower

						than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced.
						b. One time grant of 5 lakh rupees per affected family.
						c. The affected family will be provided with an annuity payment of rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be an adjusted for inflation annually).
v	Smt. Rekha	1986	W/o Sh. Manoj Kumar		Businessman	v. Subsistence grant for displaced family for period of 01 year
vi	Smt. Roshini		W/o Sh. Jagdish		Farmers	vi. Transportation cost for displaced family
vii	M/s Kanhiya Trading & Investment Co. Pvt. Ltd.	NA	NA	NA	NA	vii. Cattle shed/ Petty shops cost
						viii. One time grant to artisan, small traders and certain others.
						ix. Fishing rights
viii	M/s Surbhi Resources	NA	NA	NA	NA	x. One time resettlement allowance
ix	M/s Surbhi Resources	NA	NA	NA	NA	xi. Stamp duty and registration fees if any
x	M/s Saraswati Industries	NA	NA	NA	NA	

SURESH CHAND MEENA, Administrator (RR)